

पुस्तकालय

①
2623
12/3/08



असंशोधित

4 MAR 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन भासा
गै.सं.प्रै.सं. १५१ तिथि ११-३-०८

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । शांति, शांति ।

श्री शकील अहमद खॉ : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक कमिटी बननी चाहिए ।

अध्यक्ष : आपलोगों की भावना को ध्यान में रखते हुये पूर्व में भी इस बिन्दु पर एक निर्णय ने आसन ने लिया था जिसकी संयोजिका श्रीमती रेणु कुमारी को बनाया गया था और अभी तक उनका प्रतिवेदन भी नहीं आ सका है । माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुये इसको पूरे बिहार को इसके दायरे में कर दिया जायेगा ।

व्यवधान

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है ।

अध्यक्ष : शांति । शांति । वह भी सदन की ही कमिटी है । वह सदन की विशेष समिति है अल्प सूचित प्रश्न समाप्त हुआ । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : २१७

श्री वृषिण पटेल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड : १ उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद्, पटना ने दिनांक ३१.०१.०८ को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, मधुबनी को ५८ करोड़ रुपये आवंटित किया है

व्यवधान

खंड २ : उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद्, पटना द्वारा दिनांक ३१.०१.०८ तक ५५ करोड़ १० लाख ३७ हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

खंड : ३ उपर्युक्त खंड १ एवं २ के उत्तर के आलोक में कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामदेव महतो : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया, हल्ला के कारण ठीक से हम सुन नहीं सके । मेरा कहना है कि मधुबनी जो १ अरब रूपया गया उसमें मेरा प्रश्न है कि २६ करोड़ रूपया ही खर्च हुआ है । माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि ५५ करोड़ रूपया खर्च हो गया जबकि मेरा प्रश्न है कि २६ करोड़ रूपया ही खर्च हुआ है उस एक अरब रुपये में से ।

श्री वृषिण पटेल, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि १ अरब २५ करोड़ रूपया मधुबनी नहीं भेजा गया था । वस्तुतः बिहार शिक्षा परियोजना पर्षद्, पटना द्वारा दिनांक ३१.०१.०८ तक सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय, मधुबनी को ५८ करोड़ रूपया ही भेजा गया था जिसमें मैंने बताया कि ५५ करोड़ १० लाख ३७ हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

...

तारांकित प्रश्न : २१८

श्री रामचन्द्र सहनी, राज्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य योजनामद में भारत सरकार वन अभिकरण के माध्यम से वर्ष २००३-०४, २००४-०५, २००५-०६ एवं २००६-०७ तक बाराचट्टी वनों के विकास के लिये मात्र ५१ लाख ४७ हजार की ही राशि प्राप्त हुई है ।

खंड २ उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

खंड ३ खंड १ कि उत्तर से स्पष्ट है कि पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/4-3-08

श्री जीतन राम मांझी: अध्यक्ष महोदय, 51 लाख 45 हजार रू० खर्च होने की बात कही गयी है। यह तीन वर्षों में खर्च की गयी है या एक वित्तीय वर्ष में? यह जवाब हम नहीं सुन सके हैं।

श्री रामचन्द्र सहनी(मंत्री) महोदय, वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 इन चार वर्षों में मात्र 51 लाख 47 हजार रू० आवंटन हुआ है, जबकि इन्होंने कहा है कि चार वर्ष में चार करोड़ रू० खर्च हुए हैं, यह बात सही नहीं है।

श्री जीतन राम मांझी अध्यक्ष महोदय, जो जंगल की स्थिति है और वहां पर जो कार्य चल रहे हैं, हमने बहुत पैनी दृष्टिकोण से घुमकर देखा है, मैं मानता हूँ कि अगर 51 लाख 47 हजार रू० ही खर्च हुए हैं तो क्या यह बतलाया जा सकता है कि जो तीन प्रखंड का हमने नाम लिया है, मोहनपुर, बाराचट्टी और डोभी इसमें ये 51 लाख 45 हजार के विरुद्ध कौन-कौन सा काम हुआ है? यह बतलाने का कष्ट करेंगे, मंत्री जी।

श्री रामचन्द्र सहनी(मंत्री) महोदय, वर्ष 2003-04 में बाराचट्टी प्रखंड है, उसमें स्थल का नाम है- बरवाडीह 50 हे० भूमि में प्लानटेशन हुआ है, 50 हजार पौधा लगाये गये हैं, उसके बाद 2003-04 में ही डोभी प्रखंड में गम्हरिया स्थल पर 30 हे० में प्लानटेशन हुआ है, 2003-04 में डोभी में ही 50 हे० में इस तरह से लम्बी सूची है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य को माननीय मंत्री जी सूची दे दें।

श्री जीतन राम मांझी: अध्यक्ष महोदय, सूची तो हम ले लेंगे, ये ठीक है लेकिन अब यहां पर सिर्फ शब्द की बात आती है, मैं वैसा कोई शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन 50 हे० 30 हे० और डोभी में 50 हे०, लगभग 130 हे० में वनरोपण या कार्य करने की बात इन्होंने कही है, मैं समझता हूँ कि ये भ्रामक इनका जवाब है, विशेष रूप में हम कहना चाहते हैं कि इसको हम चुनौती देते हैं, इस प्रकार का कोई कार्य वहां नहीं हुआ है। अगर कार्य हुआ है तो क्या कार्य वहां पर है सामने, इसके लिए कोई जांच दल बनाया जा सकता है कि यह काम हुआ है या नहीं? यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री रामचन्द्र सहनी(मंत्री) काम हुआ है। जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य का कहना है काम नहीं हुआ है, वो चाहते हैं कि आप उच्चस्तरीय जांच करवा लीजिये।

श्री रामचन्द्र सहनी(मंत्री) जांच करवा लिया जा सकता है।

अध्यक्ष: किससे जांच करवायेंगे आप?

श्री रामचन्द्र सिंह(मंत्री) आप जिससे चाहेंगे।

अध्यक्ष: गया के कमिश्नर से इसकी जांच करवा ली जाय।

तारांकित प्रश्न संख्या- 219

श्री अजीत कुमार(मंत्री) 1-उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है।

2-निगम के बेड़ों में मौजूद बसों में अधिकांश पुरानी है। पटना-कटिहार जैसे लम्बे मार्गों पर पुराने बसों का परिचालन तकनीकी कारणों से सुरक्षित नहीं है। यात्रियों की